

लाइली बहनों को बड़ी सौगत

भोपाल (एजेंसी) | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में लाइली बहनों से बड़ी सौगत देते हुए कहा है कि आगमी दीपावली के बड़ी सौगत के तहत हिताही बहनों के 1500 रुपये प्रति माह की राशि नियमित दी जायेगी। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में योजना के तहत 1250 रुपये प्रति माह की राशि लाइली बहनों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत हिताही बहनों को सभी लाइली बहनों को रक्षावंधन मनाने के लिए 250 रुपये की अतिरिक्त राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। योजना के तहत चारबद्ध रूप से राशि बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रति माह तक की जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बहनों को सशक्त बनाने के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को इंदौर में संसदीय स्तर पर बड़वानों में आर्योजित कार्यक्रम को वर्तुली सम्बोधित करने के बाद मीडिया से चर्चा कर रहे थे।

म.प्र. लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025 के संबंध में कैवियट दायर

भोपाल (एजेंसी) | सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम, 2025 म.प्र. यादव पर 19 जून 2025 को अधिसंचयित किया गया है। इस संभावना के दृष्टिपात्र राज्य के किसी संस्था या शासकीय सेवक द्वारा म.प्र. लोकसेवा पदोन्नति नियम, 2025 नियम अथवा नियम के किसी भी प्रावधान पर व्यग्रण लेने के लिए उच्च न्यायालय, मुख्य खंडपीठ जबलपुर / खंडपीठ इंदौर / खंडपीठ न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग का इस अवसर पर मंत्री भी प्रावधान को चुनौती दी जाती है तो उसकी अग्रिम प्रति महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / इंदौर / न्यायालय को उपलब्ध कराई जाये। उक्त आशय की जावाहारी दो दोहरे हुए उप नियम अथवा नियम के साथ कार्य करना चाहिए। उक्त आशय की जावाहारी दो दोहरे हुए उप नियम के साथ कार्य करना चाहिए।

मंत्री श्री राजपूत ने किया सागर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह स्थल का निरीक्षण

भोपाल (एजेंसी) | डॉ. हरिसिंह गौर के क्षेत्रीय विश्वविद्यालय में 33वें दीक्षांत समारोह में क्षेत्रीय स्कूक, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने विश्वविद्यालय कल्पित प्रोफेसर नितिमा गुरु तथा विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ दीक्षांत समारोह स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि द्वारा यह सांभार्य है कि क्षेत्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रथम बार सांभार्य प्रधान रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बहुत अच्छी तैयारियों की है। मंत्री श्री राजपूत ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की तैयारियों को लेकर संतुष्टि प्रकट करते हुए उप नियम के साथ कार्य करना चाहिए। उक्त आशय की जावाहारी दो दोहरे हुए उप नियम के साथ कार्य करना चाहिए।

प्रदेश में 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

भोपाल | प्रदेश के 2383 सरकारी स्कूलों में कक्षा-9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगारान्मुखी कौशल विकास के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने विश्वविद्यालय कल्पित प्रोफेसर नितिमा गुरु तथा विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ दीक्षांत समारोह स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि द्वारा यह सांभार्य है कि क्षेत्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रथम बार सांभार्य प्रधान रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बहुत अच्छी तैयारियों की है। मंत्री श्री राजपूत ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की तैयारियों को लेकर संतुष्टि प्रकट करते हुए उप नियम के साथ कार्य करना चाहिए।

इस व्यावसायिक सरकार में भी व्यावसायिक शिक्षा के और नये ट्रेड्स शुरू किये जाने पर स्कूल शिक्षा विभाग योजना तैयार कर रहे हैं।

भोपाल | प्रदेश के 2383 सरकारी स्कूलों में कक्षा-9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगारान्मुखी कौशल विकास के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। फिल्हाल शैक्षणिक सरकार ने 12 टेक्स में कीरब 4 लाख 5 हजार विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया गया। 10 टेक्स में एग्रीकल्चर, अपेल, आंटोमाइट, ब्ल्यूटी एंड वेलेनस, बैंकिंग एंड फायरेंस सर्विसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाईटेक्यूर, हेल्थ केयर, स्टिल, फिजिकल एजुकेशन, टूरिज्म एंड हाईटेलिटी, प्लानर और आईटी विधाओं से जुड़े हैं।

इस व्यावसायिक सरकार में भी व्यावसायिक शिक्षा के और नये ट्रेड्स शुरू किये जाने पर स्कूल शिक्षा विभाग योजना तैयार कर रहे हैं।

भोपाल | प्रदेश के 2383 सरकारी स्कूलों में कक्षा-9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगारान्मुखी कौशल विकास के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। फिल्हाल शैक्षणिक सरकार ने 12 टेक्स में कीरब 4 लाख 5 हजार विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया गया। 10 टेक्स में एग्रीकल्चर, अपेल, आंटोमाइट, ब्ल्यूटी एंड वेलेनस, बैंकिंग एंड फायरेंस सर्विसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाईटेलिटी, प्लानर और आईटी विधाओं से जुड़े हैं।

इस व्यावसायिक सरकार में भी व्यावसायिक शिक्षा के और नये ट्रेड्स शुरू किये जाने पर स्कूल शिक्षा विभाग योजना तैयार कर रहे हैं।

भोपाल | प्रदेश के 2383 सरकारी स्कूलों में कक्षा-9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगारान्मुखी कौशल विकास के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी शामिल होंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ दीक्षांत समारोह स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि द्वारा यह सांभार्य है कि क्षेत्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रथम बार सांभार्य प्रधान रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बहुत अच्छी तैयारियों की है। मंत्री श्री राजपूत ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की तैयारियों को लेकर संतुष्टि प्रकट करते हुए उप नियम के साथ कार्य करना चाहिए।

भोपाल | प्रदेश के 2383 सरकारी स्कूलों में कक्षा-9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगारान्मुखी कौशल विकास के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। फिल्हाल शैक्षणिक सरकार ने 12 टेक्स में कीरब 4 लाख 5 हजार विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया गया। 10 टेक्स में एग्रीकल्चर, अपेल, आंटोमाइट, ब्ल्यूटी एंड वेलेनस, बैंकिंग एंड फायरेंस सर्विसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाईटेलिटी, प्लानर और आईटी विधाओं से जुड़े हैं।

इस व्यावसायिक सरकार में भी व्यावसायिक शिक्षा के और नये ट्रेड्स शुरू किये जाने पर स्कूल शिक्षा विभाग योजना तैयार कर रहे हैं।

भोपाल | प्रदेश के 2383 सरकारी स्कूलों में कक्षा-9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगारान्मुखी कौशल विकास के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। फिल्हाल शैक्षणिक सरकार ने 12 टेक्स में कीरब 4 लाख 5 हजार विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया गया। 10 टेक्स में एग्रीकल्चर, अपेल, आंटोमाइट, ब्ल्यूटी एंड वेलेनस, बैंकिंग एंड फायरेंस सर्विसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाईटेलिटी, प्लानर और आईटी विधाओं से जुड़े हैं।

इस व्यावसायिक सरकार में भी व्यावसायिक शिक्षा के और नये ट्रेड्स शुरू किये जाने पर स्कूल शिक्षा विभाग योजना तैयार कर रहे हैं।

भोपाल | प्रदेश के 2383 सरकारी स्कूलों में कक्षा-9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगारान्मुखी कौशल विकास के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। फिल्हाल शैक्षणिक सरकार ने 12 टेक्स में कीरब 4 लाख 5 हजार विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया गया। 10 टेक्स में एग्रीकल्चर, अपेल, आंटोमाइट, ब्ल्यूटी एंड वेलेनस, बैंकिंग एंड फायरेंस सर्विसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाईटेलिटी, प्लानर और आईटी विधाओं से जुड़े हैं।

इस व्यावसायिक सरकार में भी व्यावसायिक शिक्षा के और नये ट्रेड्स शुरू किये जाने पर स्कूल शिक्षा विभाग योजना तैयार कर रहे हैं।

भोपाल | प्रदेश के 2383 सरकारी स्कूलों में कक्षा-9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगारान्मुखी कौशल विकास के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। फिल्हाल शैक्षणिक सरकार ने 12 टेक्स में कीरब 4 लाख 5 हजार विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया गया। 10 टेक्स में एग्रीकल्चर, अपेल, आंटोमाइट, ब्ल्यूटी एंड वेलेनस, बैंकिंग एंड फायरेंस सर्विसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाईटेलिटी, प्लानर और आईटी विधाओं से जुड़े हैं।

विचार

बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के तिब्बत, शरणार्थी का दर्द

तिब्बत हमेशा अपनी आजादी के लिए लगभग 70 सालों से चीन के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने की ग़हर विश्व पटल पर लगा रहा है। इसके बाहर इस खोजना मुश्किल है, जिस पर इतिहास के किसी दोर में किसी विदेशी ताकत का प्रभाव या अधिपत्य न रहा है। तिब्बत के मामले में विदेशी प्रभाव या दखलने दारी तुलनात्मक रूप से बहुत ही सीमित समय के लिए रही थी। इस शोध पत्र में उनके स्वायत्व व चीन के अमानवीय व्यवहार जो भगवान् बौद्ध के शांति के मार्ग पर चलने के लिए तिब्बत शरणार्थी शिविरों जो भारत में अपने देश की आजादी के लिए संघर्षत हैं उस पर विश्व पटल पर मानवाधिकार हनन के लिए बहुत ही मुश्किल लेकिन उनकी आजादी की मांग करें क्योंकि इससे मानवता की रक्षा होती है। हिमालय के उत्तर में स्थित तिब्बत 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ और अशांति से भरा एक कटा हुआ इलाका है। इसका इतिहास कई तरह के ड्राटकों और परेशानियों से भरा हुआ है। 1013 ई० में नेपाल से धर्मपाल तथा अन्य बौद्ध विद्वान् तिब्बत गए। 1042 ई० में दीपंकर श्रीज्ञान अतिशा तिब्बत पहुँचे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। शाक्यवंशियों का शासनकाल 1207 ई० में प्रांभ हुआ। मंगोलों का अंत 1720 ई० में चीन के माँछु प्रशासन द्वारा हुआ। तत्कालीन साम्राज्यवादी अंगेंजों ने, जो दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभृति स्थापित करने में सफलता प्राप्त करते जा रहे थे, यहाँ भी अपनी सत्ता स्थापित करनी चाही। पर 1788-1792 ई० के गुरुओं के युद्ध के कारण उनके पैर यहाँ नहीं जम सके। परिणाम स्वरूप 19 वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थिर रखी यद्यपि इसी बीच लहाने पर कश्मीर के शासक ने तथा सिक्किम पर अंगेंजों ने आधिपत्य जमा लिया। अंगेंजों ने अपनी व्यापारिक चौकियों की स्थापना के लिये कई असफल प्रयत्न किया। इतिहास के मुताबिक तिब्बत को दक्षिण में नेपाल से भी कई बार युद्ध कराना पड़ा और नेपाल ने इसको हराया। नेपाल और तिब्बत की संस्थि के मताबिक तिब्बत को हर साल नेपाल को 5000 नेपाली रुपये हरजाना भरना पड़ा। इससे अजित होकर नेपाल से युद्ध करने के लिये चीन से मदद मांगी चीन के मदद से उसने नेपाल से छठकरा तो पा लिया लेकिन इसके बाद 1906-07 ई० में तिब्बत पर चीन ने अपना अधिकार कर लिया और याउंग ग्याइसे एवं गरटोक में अपनी चौकियाँ स्थापित की। 1912 ई० में चीन से माँछु शासन अंत होने के साथ तिब्बत ने अपने को पुनर्स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। सन् 1913-14 में चीन, भारत एवं तिब्बत के प्रतिनिधियों की बैठक शिमला में हुई जिसमें इस विशाल पठारी राज्य को भी भागों में विभाजित कर दिया गया। 23 मई, 1951 को तिब्बत ने चीन के इस विवादित समझौते पर साइन किए थे। 13 वीं शताब्दी में तिब्बत, मंगोल साम्राज्य का हिस्सा था और जीत के बाद से इसे हमेशा स्वायत्ता हासिल रही। इस सरकार की विस्तारावादी नीतियों के चलते 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया। करीब 8 महीनों तक तिब्बत पर चीन का कब्जा चलता रहा। आखिरकार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद तिब्बत अधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन मुख्यतः बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के तिब्बत सुदूर इलाके को संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। चीन में तिब्बत का दर्जा एक स्वायत्तशासी क्षेत्र के तौर पर है चीन का कहना है कि इस इलाके पर सदियों से उसकी संप्रभुता रही है।

धर्म का एक दशक: मोदी युग में सांस्कृतिक पुनर्जागरण

गजेन्द्र सिंह शेखावत

जनवरी 2024 में, जब पावन नगरी अयोध्या में सूर्योदय हुआ। सदियों से लुप्त हो चुकी प्रार्थना अब आखिरकार गुंजायमान होने लगी थी। श्री राम की अपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महज एक धार्मिक उपलधि नहीं थी। यह संयता के उद्धार का क्षण था। सदियों के आक्रमण, औपनिवेशिक विकृति और राजनीतिक देरी के बाद, मंत्रों से गुंजता हुआ और इतिहास के संदर्भ में उक्ता गया यह मंदिर शान से खड़ा था। यह सिर्फ वास्तुकला के बारे में नहीं था, यह एक धायल आत्मा के उपचार के बारे में था। श्री राम की अपनी जन्मभूमि पर वापसी ने उस राष्ट्र की आस्था को फिर से जागृत कर दिया, जिसने लंबे समय तक अपने दिल में निर्वासन की खामोशी को समेटे रखा था।



कुछ महीने पहले, भारत की प्राचीन आस्था का एक और प्रतीक चूपाप अपने सही स्थान पर लौट आया। नई संसद के उद्घाटन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेंगोल को स्थापित किया। यह एक पवित्र गजरंड है, जिसे 1947 में तमिल अधिनामों ने सत्ता के धार्मिक हस्तातरण को चिह्नित करने के लिए जवाहराल नेहरू को भेट किया था। दशकों से, इसे भुला दिया गया था, समृद्धि स्थान से बंचित किया गया, और एक प्रचलित राजदंड के तौर पर खारिज कर दिया गया था। इसकी स्थापना केवल स्मरण का कार्य नहीं था – यह एक शक्तिशाली धोषणा थी कि भारत अब खुद को उधार की आंखों से नहीं देखा। सेंगोल ने साम्राज्य के अवशेषों का नहीं, बल्कि यह पर्याप्त भर नहीं है, बल्कि यह पिछले कुछ वर्षों में भारत की अधिकारी राजनीति के नियंत्रण की वायर लेकर चला जा रहा है। इसके प्रतिनिधित्व करने के लिए जवाहराल नेहरू ने अपनी राज्य कला और आधिकारिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण अलिंगन था, जिसे उपरिवेशवाद के बाद के क्रम में लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था।

इतना ही नहीं, इन क्षणों ने एक गहरे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकेत दिया। यह एक संयतागत गतिविधि के तौर पर यात्रा परिवर्तनकारी वर्षों में सामने आएगी। 2014 में शुरू से ही यह स्पष्ट था कि मोदी सरकार के तहत संस्कृति अब सजावटी नहीं रहेगी, बल्कि यह मूलभूत होगी।

राहुल गांधी के मिशन बिहार को बड़ा झटका- अब कांग्रेस क्या करेगी?



कांग्रेस पार्टी को देशभर में मजबूत बनाने के अभियान में जुटे राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। वर्ष 2025 में वह अब तक कूल मिलाकर पांच बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। अपने इन दोरों के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार के दलाल मतदाताओं, अन्य पिछड़ी जाति के लोगों और अलंतर पिछड़ी जाति के लोगों के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं के साथ संवाद कर उन्हें साधने की कोशिश की। पार्टी संगठन को धारा और नई रफ़तार देने के लिए उन्होंने प्रदेश प्रधारी और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्षों तक को बढ़ाव दिया।

जहिर तौर पर, राहुल गांधी अपनी इन तमाम कोशिशों के जरिए बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति पर ही काम कर रहे थे। इसका एक मकसद और भी था कि बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी विपक्षी ईंडिया गठबंधन (महागठबंधन) में ज्यादा सीटें हासिल कर सकें।

लेकिन राहुल गांधी के इस %मिशन बिहार% को उनके अपने ही सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा झटका दे दिया है। लालू यादव के फॉर्मूले ने कांग्रेस पार्टी को बेचैन कर दिया है। कांग्रेस 2020 की तरह इस बार भी 70 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ा चाहती है लेकिन राजद ने इनसी सीटों देने से साफ-साफ इनकार कर दिया है। यानी अब यह तय हो गया है कि विपक्षी महागठबंधन में कांग्रेस को इस बार 2020 की तरह 70 सीटें नहीं मिलेंगी। गठबंधन और सीटों को लेकर होने वाली बैठकों की अध्यक्षता भले ही तेजस्वी यादव कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राजद ने एक गठबंधन को घोषित कर दिया है कि राजनीतिक दलों की संख्या और क्षमता के आधार पर गठबंधन में कांग्रेस को लगभग 53 सीटें ही मिल सकती हैं।

बिहार में वर्ष 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सबसे बड़े दल के तौर पर राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जबकि कांग्रेस के खाते में 70 सीटें आई थी।

एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक था। यह औपनिवेशिक प्रतीकवाद से देशी जवाबदेही की ओर बदलाव का भी प्रतीक था।

तमिलनाडु के महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के बीच 2019 की अन्योन्याचारी शिखर वार्ता की तुलना में शायद कई भी कटूतें थीं। दिल्ली के गलियारों से दूर, प्राचीन बदलाव का नाम, जो कभी पल्लव राजवंश और भारत-चीनी समुद्री संबंधों का एक संपत्र केंद्र होने के साथ-साथ दो सभ्यताओं के बीच वार्ता की पृष्ठभूमि बन गया। जब नेता चुदान्तों को काटकर बनाए गए मार्दों और पथर के खोंचों के बीच चले, तो भारत ने न केवल भूगोल, बल्कि इतिहास के नेताओं को भी प्रस्तुत किया। यह अपने सबसे सूक्ष्म और सबसे खूबसूझे रूप में उपस्थिति किया। एक गढ़ि, डिल्लीटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा आधुनिकीकरण, मंदिर जीर्णोद्धार, आदिवासी गैरव और सभ्यता से परिपूर्ण वैश्विक सभ्यता है।

इन वर्षों के दौरान, 600 से अधिक चीरी की गई कलाकृतियां विदेशी संग्रहालयों और संग्रहालयों से बाहर लाई गईं, जिनमें मूर्तियां, शिलालेख और पांडुलिपियां शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक को बापसी ने केवल अपनी नीतिगत गहराई, बल्कि अपनी आमा की बीच प्रदर्शन किया। हर प्रतिनिधिमंडल भारत के रंगों, व्यंजनों, शिलांग

